प्रकाशनार्थ

पटना, 1 मार्च। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) द्वारा आज ''सामाजिक संरक्षण का सुदृढ़ीकरण'' शीर्षक वेबिनार का आयोजन किया गया। पैनल का संचालन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की प्रिया नंदा ने किया। पैनल में बिहार सरकार के अरविंद चौधरी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रांची विश्वविद्यालय के ज्यां द्रेज़, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मैत्रीश घटक, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की सुधा नारायण ने भागीदारी की।

विगत कई दशकों से भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर वस्तु और नकद अंतरण के अनेक कार्यक्रम चलाए हैं जिनका लक्ष्य समाज कल्याण के परिणामों में सुधार लाना है। जहां भारत में सामाजिक संरक्षण के कार्यक्रमों से गरीबी घटाने में काफी मदद मिली, वहीं उनमें समस्याएं भी रही हैं और इन कार्यक्रमों के परिणामों के प्रभाव पर विश्वसनीय साक्ष्य सीमित ही रहे हैं। इस वेबिनार में असुरक्षित आबादी की पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों और नीतिगत समाधानों पर चर्चा की गई।

ज्यां द्रेज़ : पोषण संबंधी सूचकों में कमी पर दो कारकों का असर पड़ा हो सकता है। एक, बाल बजट में कमी, अर्थात समेकित बाल विकास सेवा के बजट में कमी जो स्थिर मूल्य पर 7 वर्ष पहले की अपेक्षा 40 प्रतिशत कम है। दूसरे, 2016 से शुरू हुआ आर्थिक संकट जो कल्याणमूलक कार्यक्रमों को प्रभावित करता रहा है। उन्होंने सूखा राशन (टीएचआर) और नकद के बीच चुनाव करने पर भी टिप्पणी की और कहा कि सूखा राशन महज अंतरण कार्यक्रम नहीं है। यह मूल्यवान संस्थान - आंगनवाड़ी केंद्रों - द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधि भी है जिसमें समाज के सदस्य (आंगनवाड़ी सेविकाएं) भी शामिल होते हैं। इससे समुदाय को मान्यता मिलती है और महिलाएं चर्चा में आती हैं।

सुधा नारायण : नकद बनाम सूख राशन कार्यक्रम की एक चुनौती महिलाओं की कम संलग्नता, अर्थात बैंकों तक पहुंचने, निर्णय लेने, और परिवार में खाना के वितरण की आजादी में कम संलग्नता है। नकद बनाम सूखा राशन के बारे में वैश्विक प्रमाणों से पता चलता है कि इनके लक्ष्य और विषयवस्तु स्वतंत्र नहीं हैं। भावी तरीका नकद और (पका खाना सहित) सामग्री के अंतरण का संयोजन हो सकता है। उन्होंने 3 मुख्य चिंताओं पर जोर दिया। एक, भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में प्रतिबद्धता में कमी की चिंता जबकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। दूसरा, केंद्र और राज्य द्वारा वित्तपोषण की समस्या कि बोझ कौन उठाएगा, क्योंकि कुछ सुचारु ढंग से चल रही सामाजिक प्रणालियों का आरंभ राज्यों ने किया है। और तीसरा, राज्यों के बीच जानना-सीखना कम ही होता है और इस संबंध में कुछ होने के बहुत साक्ष्य नहीं मिलते हैं।

मैत्रीश घटक : सुब्रामनियन-फेलमैन द्वारा प्रस्तुत कल्याणमूलक अर्थशास्त्र के आलेख को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग और रसोई गैस योजना की स्वीकार्यता रही है लेकिन अन्य योजनाओं का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। उनकी यह भी टिप्पणी थी कि पोषण पर एनएफएचएस-5 के सूचक गंभीर स्थिति में हैं और गरीबों की संख्या में कमी आती गई है जिसके नीतिगत झटके, नोटबंदी और कोविड आदि अनेक कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान समाज कल्याण पर अतिरिक्त खर्च की जरूरत है और भारत सरकार द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा देशों की तुलना पर हाल में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रभावी नहीं दिखता है। उन्होंने समाज कल्याण

योजनाओं पर यह भी कहा कि हमें योजनाओं के व्यय और लाभों पर और विभिन्न योजनाओं की पूरकता पर, जैसे कि नकद और सूखा राशन के संयोजन पर विचार करना होगा। साथ ही, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत समावेशी विकास लाभांश देने की बात पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना अभी चल ही रही है, हम तो बस आबंटन को दूना करने और सभी को इस व्यापक योजना के दायरे में लाने की बात कह रहे हैं जिसमें बहिष्करण संबंधी त्रुटियों से बचने के लिए सभी को शामिल किया जाय।

अरविंद चौधरी : कोविड-19 महामारी के दौरान संकट का समय था और इसके आरंभिक दिनों में निर्माण तथा अनेक अन्य गतिविधियों को स्वीकृति नहीं थी। लेकिन मनरेगा के मूल ढांचे को स्वीकृति दी गई और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद हमने इसका जबर्दस्त अभ्यास किया कि लोगों के पुनः लौट जाने के मामले में कैसे तैयार रहा जाय। एक रणनीति उनसे कैरेंटाइन केंद्रों में संपर्क बिंदु पर मिलने की थी। यहां हमने सुनिश्चित किया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए आधार और जॉब कार्डों के निबंधन में सहयोग किया गया है। शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक अभियान था, कोई नया कार्यक्रम नहीं। लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए सारे कार्यों में तेजी लाई गई। हालांकि यह कोई नई योजना नहीं थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काम की उपलब्धता पर इसका असर पड़ा और संकट से निपटने में इससे काफी हद तक मदद मिली।

(अंजनी कुमार वर्मा)